Panel on Infrastructure Privatisation

1880. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a panel on infrastructure privatisation; and

(b) if so, what will be the terms of reference of the panel?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Employment in Gujarat and Rajasthan

1881. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to create employment opportunities for youths living in backward and tribal areas of Gujarat and Rajasthan;

(b) if so, the details thereof and criteria and specific particulars of schemes which have been adopted by Government for the Gujarat State;

(c) the details of the allocation of funds for each district of both the States, separately, during the Eighth Plan period; and

(d) if so, by when these schemes are likely to be implemented in each district of Gujarat and Rajasthan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) No specific proposal has been received in the Planning Commission in this regard.

(b) to (d) Do not arise.

जिलाधीश, कुल्लू को उपलब्ध करवाई गई धनराशि

1882 **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जिलाधीश, कुल्लू को पांच लाख रुपये उपलब्ध कराये गये थे, यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित सभी योजनाओं में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ,

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनायें अब तक पूरी की जा चुकी हैं और जिलाधीश द्वारा कार्य करने वाली किन-किन एजेंसियों को किन-किन तिथियों को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई थी ;

(ग) किन-किन विभागों द्वारा इस धनराशि का पूर्णरूप से इस्तेमाल किया गया है और ऐसे विभाग कौन-कौन से है जिन्होंने न तो इस धनराशि का इस्तेमाल किया है न ही समय रहते जिलाधीश और प्रश्नकर्ता को उन कारणों से अवगत करवाया है जिनके फलस्वरूप निर्माण-कार्यों को हाथ में नहीं लिया जा सका; और

(घ) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने न तो योजना पर कोई खर्च ही किया है और न ही समय रहते जिलाधीश और प्रश्नकर्ता को निर्माण कार्य आरम्भ न करने के कारणों से अवगत कराया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वित्तीय वर्ष 1993-94 में जिलाधीश, कुल्लू को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये थे। सभी योजनाओं पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जानकारी विवरण I **(नीचे देखिए)** में दर्शायी गयी है।

(ख) जिलाधीश कुल्लू द्वारा जिन-जिन तिथियों को जिन-जिन कार्यान्वयन एजेंसियों को जितनी-जितनी धनराशि दी गई है उसे विवरण II **(नीचे देखिए)** में दर्शाया गया है।

(ग) एवं (घ) अभी किसी भी विभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी ने धनराशि का पूर्ण उपयोग नही किया है। जिन विभागों/कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा धनराशि का उपयोग नही किया गया उनके बारे में जानकारी विवरण-III में दी गयी है।

विवरण-I

माननीय सांसद सदस्य राज्य सभा श्री महेश्वर सिंह द्वारा अनुशंसा की गई स्वीकृत स्कीमों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र०सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत की गई राशि	कार्यान्वयन एजेन्सी	दिनांक 10-11-94 को हुई बैठक में कार्यान्वयन एजेंन्सियों की रिपोर्ट के अनुसार कार्य की सूची
1	2	3	4	5
1	निर्माण सामुदायिक भवन, चकुरठा ग्रा० पं०, चकुरठा	50,000	ख०वि०अ० बन्जार	काम चल रहा है। दिसम्बर मास में पूर्ण होने की संभावना बताई गई है।

1	2	3	4	5
2	सरसाड़ी से चौग गांव तक सड़क का निर्माण ।	50,000	अधिशाषी अभियंता लो० नि० वि० मंडल-1, कुल्लू	काम चल रहा है। दिसम्बर मास में पूर्ण होने की संभावना बताई गई है ।
3	छरोढ़नाला से भरेठा गांव तक सड़क का निर्माण।	50,000	—वही—	—वही—
4	नरसिंह युवक मण्डल (रजि०) जलूग्रां का भवन निर्माण ।	10,000	ख० वि० अ०, कुल्लू	राशि कम है। अतः इससे कार्य नहीं होगा । पूरी (और) राशि मिलने पर कार्य किया जायेगा ।
5	गांव चनायडी डा० बजा-हुरा कोठी शैंशर तह० सैंज में कम्युनिटी हाल का निर्माण ।	20,000	ख० वि० अ०, बंजार	—वही—
6	मनुकृता केन्द्र, मनाली को सांस्कृतिक भवन बनाने हेतू ।	11,000	ख० वि० अ०, नगर	कार्य दिसम्बर मास में पूर्ण होने की संभावना ।
7	गांव सैंज में स्टेडियम का निर्माण ।	50,000	ख० वि० अ०, कुल्लू	—वही—
8	गांव बागी श्याड़ी से खाड़न तक खच्चर रास्ता ।	40,000	ख० वि० अ०, बंजार	—वही—
9	गांव छरोड़नाला से बड़ोगी सड़क का निर्माण ।	50,000	अधिशाषी अभियंता लो० नि० वि० मण्डल-I, कुल्लू	कार्य चल रहा है ।
10	गांव शारनी कोठी चौंग की हरिजन बस्ती हेतू पेय जल का प्रावधान ।	20,000	अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग, कुल्लू	—वही—
11	कश्यप महिला मण्डल भवन करेरी का निर्माण ।	40,000	ख० वि० अ०, कुल्लू	कार्य दिसम्बर मास में पूर्ण होने की संभावना ।
12	गांव उड़सू में सराय का निर्माण ।	9,000	—वही—	राशि कम है । पूरी राशि मिलने पर कार्य होगा ।
13	सैंज से देऊरी गांव तक सड़क का निर्माण ।	1,00,000	वन मंडल अधिकारी, बन्जार	सड़क में बहुत सी तृतीय श्रेणी फोरेस्ट लैण्ड है । अतः यह विवाद हल होने पर कार्य हो सकेगा ।

विवरण-II

स्वीकृति पत्र की संख्या व तिथि	कार्यान्वयन एजेन्सियों का नाम	जितनी स्कीमों हेतु धन दिया	जितनी धनराशि दी गई
1372 (2-5-94)	वन मण्डल अधिकारी, बन्जार ।	1 (एक)	1,00,000
1377 (2-5-94)	खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू ।	4 (चार)	1,09,000
1382 (2-5-94)	अधिशासी अभियंता, लो० नि० वि० डिविजन-I, कुल्लू ।	3 (तीन)	1,50,000
1387 (2-5-94)	खण्ड विकास अधिकारी, बन्जार ।	3 (तीन)	1,10,000
1392 (22-4-94)	खण्ड विकास अधिकारी, नगर स्थित कटरनई ।	1 (एक)	11,000
1397 (2-5-94)	अधिशासी अभियन्ता, लो० नि० वि०, कुल्लू ।	1 (एक)	20,000
	योग :	13 (तेरह)	5,00,000

नोट : उक्त कार्यान्वयन एजेन्सियों को जिन स्कीमों हेतु धन दिया गया है उन स्कीमों का विवरण, राशि व कार्य कब पूर्ण होगा का ब्यौरा साथ संलग्न है ।

विवरण-III

विभाग/कार्यान्वयन एजेंसी का विवरण जिनके द्वारा धन का उपयोग नहीं किया गया है।

1. वन मण्डल अधिकारी,
   सराज स्थित बन्जार ।

उक्त अधिकारी ने अपने पत्र संख्या-462 दिनांक 27-6-94 द्वारा जिलाधीश को अवगत करवाया कि माननीय सांसद महोदय द्वारा सुझाये गए कार्य "सेज से देऊरी" गाँव तक 8 कि०मी० सड़क के निर्माण हेतु धनराशि बहुत कम है। दूसरे इस कार्य में बहुत मात्रा में तृतीय श्रेणी वन भूमि लगती है तथा फारेस्ट कन्सरवेशन ऐक्ट 1980 के अंतर्गत बहुत सी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी जिसके लिये 5-6 मास का समय लग सकता है। अतः यह धनराशि इस वित्तीय वर्ष में उपयोग में नही लाई जा सकती है।

जिलाधीश ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 22-7-94 द्वारा उक्त तथ्यों से माननीय सांसद को अवगत करा दिया था तथा स्कीम के परिवर्तन और नई स्कीम सुझाने का अनुरोध भी किया था।

2. खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू ।

3. खण्ड विकास अधिकारी, बन्जार ।

उक्त अधिकारियों ने दिनांक 9-8-94 को बताया कि युवक मण्डल, कम्युनिटी हाल, सराय निर्माण हेतु स्कीमों में बहुत ही कम धनराशि की अनुशंसा की गयी है तथा प्राक्कलन की लागत के अनुसार पूरी धनराशि मिलने पर ही कार्य शुरु करना संभव हो पायेगा। खण्ड विकास अधिकारियों के पैसे की इस कमी की बात को उक्त अ० शा० पत्र द्वारा सांसद महोदय को भी अवगत करा दिया गया था।

Centrally Sponsored Schemes in Gujarat

1883. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have undertaken any study in the State of Gujarat to undertake the effective implementation of the various Centrally Sponsored Schemes;

(b) if so, the details thereof: and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) The Planning Commission has not undertaken any study in the State of Gujarat to undertake the effective implementation of the various Centrally Sponsored Schemes. Centrally sponsored schemes are formulated by Administrative Ministries in consultation with State Governments and these are monitored by the Administrative Ministries concerned. The Planning Commission generally reviews the implementation of Plan Schemes during the Annual Plan discussions with the States.

Lowest Annual Assistance to Gujarat

1884. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the per capita annual assistance being provided to Gujarat is the lowest among the States;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) The per capita annual assistance being provided to Gujarat is not the lowest among the States.

(b) and (c) Do not arise.

Power Transmission Scheme in Gujarat

1885. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether there is any power transmission scheme/projects approved by Government for the State of Gujarat so far; and

(b) if so, the details thereof and the funds earmarked for the proposed projects?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) For projects costing Rs. 100 crore and above in the Power Sector, investment approval is required to be given by the Planning Commission. In the first three years of the Eighth Plan, no such power transmission scheme/project has been accorded investment approval by the Planning Commission so far.

(b) Does not arise.

Poverty Alleviation Scheme in Orissa

1886. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state: